

MOST URGENT

From

The Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Home Department

To

1. The Director General of Police, Haryana, Panchkula.
2. The Director of Prosecution (General), Panchkula.
3. All the District Magistrates in Haryana.
4. All the Inspector Generals of Police in Haryana.
5. All the Commissioners of Police in Haryana.
6. All the Superintendents of Police in Haryana.
7. All the Deputy Commissioner of Police in Haryana.
8. All the District Attorneys/Deputy District Attorneys/Assistant District Attorneys in Haryana

Memo No. 12/264/2019-4HGIV
Dated Chd, the 20-02-2025

Subject: Notification of "Haryana Summons (Service through Electronic Communication) Rules, 2025."

Kindly refer on the subject noted above.

2. The State Government has issued the Notification of "Haryana Summons (Service through Electronic Communication) Rules, 2025" vide No. 12/264/2019-4HG-IV, dated 14-02-2025.

3. You are, requested to download the notification from the website of Home Department i.e homeharyana.gov.in for information and further necessary action.

Dilbag Singh

Superintendent Home-IV
for Additional Chief Secretary to Govt. Haryana,
Home Department



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 33-2025/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, FEBRUARY 14, 2025 (MAGHA 25, 1946 SAKA)

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 फरवरी, 2025

संख्या 12/264/2019-4 एच0.जी0-IV.— भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 46) की धारा 64 की उप-धारा (1) तथा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से समन की तामील सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) ये नियम हरियाणा समन (इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से तामील) नियम, 2025 कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।
 - (क) "जिला नोडल एजेंसी" से अभिप्राय है, इन नियमों के नियम 5 के अधीन गठित जिला नोडल एजेंसी;
 - (ख) "इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर" से अभिप्राय है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम 21) की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक तकनीक के माध्यम से अभिदाता या न्यायालय द्वारा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का अधिप्रमाणन और इसमें डिजिटल हस्ताक्षर भी शामिल हैं। इसके अलावा, जब इलेक्ट्रॉनिक रूप में उत्पन्न किसी प्रक्रिया या रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के माध्यम से अधिप्रमाणित किया जाता है, तो इसे उस व्यक्ति के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किया गया समझा जाएगा, जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किए हैं;
 - (ग) "संहिता" से अभिप्राय है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 46);
 - (घ) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;
 - (ङ) "राज्य नोडल एजेंसी" से अभिप्राय है, इन नियमों के नियम 3 के अधीन गठित राज्य नोडल एजेंसी;
 - (च) "समन" से अभिप्राय है, इस संहिता के अधीन न्यायालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से जारी किए गए समनों सहित सभी समन;
 - (छ) "समन सेल" से अभिप्राय है, इन नियमों के नियम 7 के अधीन गठित समन सेल।

- (2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो क्रमशः संहिता, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 45) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम 21) में उन्हें दिया गया है।
- राज्य नोडल एजेंसी।
3. निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक राज्य नोडल एजेंसी होगी, अर्थात्:—
- (1) पुलिस महानिरीक्षक (कानून और व्यवस्था) : अध्यक्ष
- (2) अभियोजन विभाग के अपर निदेशक (मुख्यालय)/ जिला न्यायवादी (मुख्यालय) : सदस्य
- (3) सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) : सदस्य सचिव
- राज्य नोडल एजेंसी की भूमिका।
4. (1) राज्य नोडल एजेंसी जिला नोडल एजेंसियों के कामकाज की निगरानी और समीक्षा करेगी।
- (2) राज्य नोडल एजेंसी प्रत्येक मास कम से कम एक नियमित बैठक करेगी।
- (3) राज्य नोडल एजेंसी, समय-समय पर, संहिता या इन नियमों से अनअसंगत ऐसे निर्देश या दिशा-निर्देश या स्पष्टीकरण जारी कर सकती है, जो इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से समन को दक्ष और प्रभावी तामील के लिए आवश्यक हों।
- जिला नोडल एजेंसी।
5. राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला नोडल एजेंसी होगी, जो निम्नलिखित अधिकारियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—
- (1) पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय)/पुलिस अधीक्षक : अध्यक्ष
- (2) उप निदेशक अभियोजन/सहायक निदेशक अभियोजन/जिला न्यायवादी : सदस्य
- (3) सहायक पुलिस आयुक्त/पुलिस उपाधीक्षक (समन प्रकोष्ठ का पर्यवेक्षी अधिकारी) : सदस्य सचिव
- जिला नोडल एजेंसी के कर्तव्य।
6. (1) जिला नोडल एजेंसी समन सेल के कामकाज की निगरानी और समीक्षा करेगी।
- (2) जिला नोडल एजेंसी सुनिश्चित करेगी कि समन सेल द्वारा समन उचित रूप में और समय पर तामील किए जाएं।
- (3) जिला नोडल एजेंसी, प्रत्येक मास कम से कम एक बार, नियमित बैठक करेगी।
- (4) जिला नोडल एजेंसी समनों की उचित और समय पर तामील करने हेतु राज्य नोडल एजेंसी द्वारा जारी किए गए निर्देशों और दिशा-निर्देशों इत्यादि और इन नियमों और संहिता के उपबन्धों से संगत समन सेल को यथावश्यक अनुदेश जारी कर सकती है।
- समन सेल।
7. संहिता के अधीन न्यायालय द्वारा जारी किए गए समन की समय पर तामील सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर एक पुलिस अधिकारी, जो उप-निरीक्षक की पदवी से नीचे का न हो, की अध्यक्षता वाली एक समन सेल होगी और इसमें पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मचारी शामिल होंगे।
- समन सेल के कर्तव्य।
8. (1) समन सेल, समन का उचित और यथासमय तामील करने के लिए जिम्मेदार होगी।
- (2) समन सेल, जिला के प्रत्येक पुलिस थाना के लिए सभी समनों का अभिलेख पंजाब पुलिस नियम, 1934, हरियाणा राज्याथ के नियम 22.55 के अधीन विनिर्दिष्ट रजिस्टर संख्या V, भाग-II में अनुरक्षित करेगी, जिसमें निम्नलिखित सूचना शामिल है, अर्थात्:—
- (i). समन किए गए व्यक्ति का नाम;
- (ii). समन किए गए व्यक्तियों का पत्राचार और स्थायी पता;
- (iii). समन किए गए व्यक्ति के पिता/माता/पति-पत्नी/परिवार के व्यस्क सदस्य का नाम;
- (iv). समन किए गए व्यक्ति की आधार संख्या;
- (v). समन किए गए व्यक्ति की मोबाइल संख्या;
- (vi). ई-मेल आई.डी. (यदि कोई हो);
- (vii). समन जारी करने वाले न्यायालय का नाम;
- (viii). सी.एन.आर.संख्या (यदि कोई हो), एफ.आई.आर.संख्या, पुलिस थाना इत्यादि सहित मामले के विवरण;
- (ix). समन जारी करने की तिथि;
- (x). समन सेल द्वारा समन प्राप्त करने की तिथि;
- (xi). समन में उल्लिखित अनुसार न्यायालय में पेश होने की तिथि;

- (xii). तामील किया गया है या नहीं। यदि तामील नहीं किया गया है, तो उसके कारण;
- (xiii). समन तामील करने की तिथि;
- (xiv). जिस व्यक्ति को समन तामील गया था, उसके विवरण;
- (xv). तामील करने का ढंग (व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से);
- (xvi). इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के साधनों का नाम;
- (xvii). टिप्पणी, यदि कोई हो।

(3) इस नियम के अधीन रजिस्टर या तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में या भौतिक रूप में या दोनों रूपों में रखा जाएगा।

9. पुलिस अधिकारी के अलावा, समन, बेलिफ या आदेशिका तामीलकर्ता या न्यायालय के किसी अन्य अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा, उक्त प्रयोजन के लिए पदाविहित किसी लोकसेवक द्वारा भी तामील किया जा सकता है।

समन तामील करने हेतु अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी।

10. (1) संहिता के अधीन जारी किए गए समन, जहां तक संभव हो सके, संहिता के सुसंगत उपबन्धों के अधीन यथाविहित अनुसार तामील किए जाने चाहिए।

इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा समन की तामील।

(2) इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा समन करने की तामील का स्वरूप और रीति ऐसी होगी, जो राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ई-समन एप्लिकेशन या उस द्वारा समय-समय पर विकसित और अद्यतन की गई किसी अन्य सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन के माध्यम से विनिर्दिष्ट की जाए।

(3) जहां ई-समन एप्लिकेशन से अन्यथा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से समन तामील किया जाता है, तो वहां समन की डिलीवरी को दर्शाने वाली एप्लिकेशन के स्क्रीन शॉट/फोटो को भी समन की तामील की पावती के रूप में माना जाएगा।

(4) इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से समन की तामील की पावती को, संहिता की धारा 64 की उप-धारा (3) के अर्थ के भीतर रसीद के रूप में माना जाएगा, जिसे, आगे, समन की तामील के प्रमाण के रूप में माना जाएगा।

(5) यदि समन किए गए व्यक्ति से संबंधित ईमेल पता/संपर्क संख्या या संदेश एप्लिकेशन उपलब्ध नहीं हैं, तो समन तामील करने वाला कर्मचारी/व्यक्ति, नियम 8 के अधीन विहित प्ररूप में टिप्पणी के कॉलम में, इस संबंध में एक प्रविष्टि दर्ज करेगा और इलेक्ट्रॉनिक ढंग में जारी किए गए समन के दोहरी प्रति में प्रिंटआउट लेने के बाद, संहिता के अध्याय VI के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार इसे निष्पादित करेगा।

11. इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्व राज्य सरकार द्वारा समनों की तामील के संबंध में जारी किए गए कोई नियम, नीति या दिशानिर्देश इन नियमों से अगसंगत उनके विस्तार की सीमा तक, इराके द्वारा निरसित किए जाते हैं।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

डा० सुमिता मिश्रा,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Notification

The 14th February, 2025

No. 12/264/2019-4HG-IV.— In exercise of the powers conferred under sub-sections (1) and (2) of section 64 of the **Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023** (Central Act 46 of 2023), the Governor of Haryana hereby makes the following rules for ensuring service of summons through electronic communication, namely: -

- | | | | |
|------------------------------|----|-----|--|
| Short title and commencement | 1. | (1) | These rules may be called the Haryana Summons (Service Through Electronic Communication) Rules, 2025. |
| | | (2) | They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette. |
| Definitions | 2. | (1) | In these rules, unless the context otherwise requires, - |
| | | (a) | “District Nodal Agency” means the District Nodal Agency constituted under rule 5 of these rules; |
| | | (b) | "electronic signature" means authentication of any electronic record by a subscriber or court, by means of an electronic technique specified in the Second Schedule of the Information Technology Act, 2000 (Central Act 21 of 2000) and includes digital signature. Also, when a process or report generated in electronic form is authenticated by means of electronic signature, it shall be deemed to be authenticated by signature of the person who affixed the electronic signature; |
| | | (c) | “Sanhita” means the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act 46 of 2023); |
| | | (d) | “State Government” means the Government of the State of Haryana in the Administrative Department; |
| | | (e) | “State Nodal Agency” means the State Nodal Agency constituted under rule 3 of these rules; |
| | | (f) | "summons" means every summon including summons through electronic communication, issued by a Court under the Sanhita; |
| | | (g) | “summons cell” means the summons cell as constituted under rule 7 of these rules. |
| | | (2) | Words and expressions used herein and not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Sanhita, the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Central Act 45 of 2023) and the Information Technology Act, 2000 (Central Act 21 of 2000). |
| State Nodal Agency | 3. | | There shall be a State Nodal Agency comprising of the following officers namely: - |
| | | (1) | Inspector General of Police (Law and Order) : Chairperson |
| | | (2) | Additional Director (HQ)/District Attorney (HQ) of Prosecution Department : Member |
| | | (3) | Assistant Inspector General of Police (Administration) : Member Secretary |
| Role of State Nodal Agency | 4. | (1) | The State Nodal Agency shall monitor and review the working of the District Nodal Agencies. |
| | | (2) | The State Nodal Agency shall hold regular meetings, at least once in every month. |
| | | (3) | The State Nodal Agency may issue, from time to time, such directions or guidelines or clarification, not inconsistent with the Sanhita or these rules, as may be necessary for efficient and effective service of summons through electronic communication. |

5. There shall be a District Nodal Agency in every District in the State consisting of the following officers, namely: - District Nodal Agency
- (1) Deputy Commissioner of Police (HQ)/Superintendent of Police : Chairperson
 - (2) Deputy Director of Prosecution/Assistant Director of Prosecution/District Attorney : Member
 - (3) Assistant Commissioner of Police/Deputy Superintendent of Police (Supervisory Officer of Summons Cell) : Member Secretary
6. (1) The District Nodal Agency shall monitor and review the working of summons cell. Role of District Nodal Agency
 (2) The District Nodal Agency shall ensure that summons are served properly and timely by the summons cell.
 (3) The District Nodal Agency shall hold regular meetings, at least once in every month.
 (4) The District Nodal Agency may issue instructions to the summons cell as may be necessary, in consonance with the directions or guidelines etc. issued by the State Nodal Agency and the provisions of these rules and the Sanhita, for proper and timely service of summons.
7. There shall be a summons cell at the District level headed by a police officer not below the rank of Sub-Inspector and shall comprise of sufficient number of police officials, to ensure the timely service of summons issued by the Courts under the Sanhita. Summons cell
8. (1) The summons cell shall be responsible for proper and timely service of summons. Duties of summons cell
 (2) The Summons Cell shall maintain a record of all summons for each police station in the district in Register no. V Part II prescribed under rule 22.55 of the Punjab Police Rules, 1934 as applicable to the State of Haryana including the following information, namely: -
- (i) Name of the person summoned
 - (ii) Correspondence and permanent address of the persons summoned
 - (iii) Name of father/mother/spouse/adult member of family of person summoned
 - (iv) Aadhar number of the person summoned
 - (v) Mobile number of the person summoned
 - (vi) E-mail ID (if any)
 - (vii) Name of the Court issuing the summon
 - (viii) Particulars of case including CNR Number (if any), FIR Number, Police Station etc.
 - (ix) Date of issue of summon
 - (x) Date of receiving of summon by the summons cell
 - (xi) Date of Appearance in the court, as mentioned in the summon
 - (xii) Whether served or not. If not served, reasons thereof
 - (xiii) Date of service of summon
 - (xiv) Details of the person upon whom the summon was served
 - (xv) Mode of service (physically or through electronic communication)
 - (xvi) Name of the means of electronic communication
 - (xvii) Remarks, if any.
- (3) The register under this rule shall be maintained either in electronic form or physical form or both.
9. Besides a police officer, summons may also be served by the Bailiff or Process Server or other officer of the Court, or any public servant designated for the said purpose by the State Government. Officers or official authorized to serve summon

Service of
summons by
electronic
communication

10. (1) Summons issued under the Sanhita should be served by electronic communication, as far as practicable, as prescribed under relevant provisions of the Sanhita.

(2) The form and manner of service of summons by electronic communication may be as prescribed by the National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India, through the e-summons application or any other software application developed and updated by it, from time to time.

(3) Where a summon is served by way of any electronic communication other than e-summon application, the screenshot/photo of the application reflecting delivery of the summon may also be treated as acknowledgement of service of the summon.

(4) Acknowledgement of the service of summons through electronic communications shall be treated as receipt within the meaning of sub-section (3) of section 64 of the Sanhita which shall further be treated as a proof of service of summons.

(5) In case email address/contact number or messaging application relating to the person summoned are not available, the summon serving official/person shall make an entry in this regard in the remarks column in the format prescribed under rule 8 and after taking printouts in duplicate of the summon issued in electronic mode, shall execute the same in accordance with the procedure prescribed under Chapter VI of the Sanhita.

Repeal and
saving

11. Any rule, policy or guidelines regarding service of summons issued by the State Government prior to the commencement of these rules are hereby repealed to the effect and extent to their inconsistency with these rules.

DR. SUMITA MISRA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Home Department.